भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2213

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड

2213. डॉ. गणपथी राजकुमार पी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों में कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में केन्द्रीकृत सार्वजनिक वितरण कार्ड बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या गरीब लोगों के लिए बने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्डों को गिरवी रखने के कोई उदाहरण सामने आए हैं; और

(च) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्डों के इस तरह गिरवी रखे जाने की प्रथा बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लागू किया गया है। यह अधिनियम प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।

...2/-

(ग) और (घ): देश में केंद्रीकृत सार्वजनिक वितरण कार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के रूप में जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी संचालित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपॉश) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्रता का खाद्यान्न उठाने का अधिकार दिया गया है। घर पर परिवार भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा उठा सकते हैं।

(ङ) एवं (च): जी नहीं, पीडीएस कार्डों को गिरवी रखने का कोई मामला नहीं है।

*****